New laws from today 1st July 2024

On the draw

MIKA AZIZI

BHARATIYA
NYAYA
SANHITA
2023
BNS
BHARATIYA
NAGARIK
SURAKSHA
SANHITA
2023
BNSS
BHARATIYA
SAKSHYA
ADHINIYAM
2023
BSA

पहला	दूसरा	तीसरा
1860	1898	1872
में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब **भारतीय न्याय संहिता 2023**	में बने सीआरपीसी की जगह अब **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023**	में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब **भारतीय साक्ष्य संहिता 2023**

ट्रायल के मामले

- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था।
- किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी।
- अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैरमौजूदगी में भी ट्रायल होगा।
- गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है।
- अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा।

- गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है।

- अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा।
- मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा।
- फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी।
- दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी NGO या कोई संस्थान दया याचिकाएं दाखिल करता था।

एक्सीडेंट के मामले

- वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी।
- हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी।
- स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है।
- सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी।

गंभीर अपराध

- नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद या फांसी होगी।
- पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63, 69 होगी।
- हत्या की धारा 302 थी, अब यह 101 होगी।
- गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी।
- मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी।

भारतीय न्याय संहिता में क्या बड़े बदलाव हुए..

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं।
- ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान।
- डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं।
- IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है।
- 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है।
- 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है।
- छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

Crime and punishment

The new Bharatiya Nyaya Sanhita has 358 Sections against the 511 in the Indian Penal Code that it replaces. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita replaces the Code of Criminal Procedure, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam comes in place of the Indian Evidence Act

ISTOCKPHOTO

What is new?

- Provision for **Zero FIR** allowing filing of a first information report at any police station, regardless of jurisdiction
- **Online registration** of police complaints and mandatory videography of crime scenes for all heinous crimes
- A person can now report incidents by **electronic communication**, without the need to visit a police station
- Judgment in criminal cases has to come **within 45 days** of completion of the trial
- Provisions against false promise of marriage, gang rape of minors and **mob lynching**
- Statement of a woman rape victim will be recorded by a woman police officer **in the presence of her guardian or relative**
- Death sentence or life imprisonment for **gang rape of a minor**
- **Sedition** has been replaced with 'secession' or 'act against the country's sovereignty, unity and integrity'

HOW IPC SECTION NUMBERS HAVE CHANGED IN BHARATIYA NYAYA SANHITA

Provision	IPC	BNS
Punishment for murder	302	103
Cruelty against a married woman	498A	85
Rape	375	63
Sedition	124 A	152
Defamation	499	356
Cheating	420	318
Dowry death	304B	80
Criminal Conspiracy	120 A	61
Attempt to murder	307	109
Promoting enmity between different groups	153A	196
Imputations, assertions prejudicial to national integration	153B	197
Statements conducing to public mischief	505	353
Defamation	499	356
Sexual harassement	354A	75
Outraging the modesty of a woman	354	74
Criminal intimidation	503	351
Public nuisance	268	270
Gang rape	376D	70(1)

EXPEDITING JUSTICE

FIR REGISTRATION: To be recorded within three days for complaints submitted through electronic communication

MEDICAL EXAMINATION REPORTS: In sexual offences to be forwarded within seven days

VICTIM/INFORMANT UPDATES : Updates to victims/informants about investigation status within 90 days

FRAMING OF CHARGE: Magistrate required to frame charges within 60 days from the date on which documents are supplied

TRIAL IN ABSENTIA: Courts empowered to initiate trial in absentia against declared offenders within 90 days from framing charges

COURT DECISION: Court decisions on acquittal or conviction within 30 days post-argument completion, with an extension of up to 60 days for recorded reasons